भारत सरकार

योजना मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 787

दिनांक 02.12.2024 को उत्तर देने के लिए

सतत विकास लक्ष्य

787. **श्री कार्तिकेय शर्मा**:

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 17 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में से प्रत्येक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्धता बढ़ाने हेतु पहल की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी)- वार पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने की प्रक्रिया में सरकार द्वारा किन-किन बाधाओं की पहचान की गई है और उनके समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इन प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में राज्य सरकारों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय;
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय एवं
राज्यमंत्री, संस्कृति मंत्रालय

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) और (ग) भारत सरकार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) 17 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। प्रमुख पहलों में एसडीजी लक्ष्यों को प्रासंगिक योजनाओं और विभागों के साथ संरेखित करना, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित विशिष्ट एसडीजी विजन दस्तावेज तैयार करना, जिला और ब्लॉक स्तर तक संकेतक रूपरेखा का विस्तार करना, स्थानीयकरण को बढ़ावा देने के लिए एसडीजी समन्वय एवं त्वरण केंद्रों की स्थापना करना और

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के बजट को एसडीजी के साथ एकीकृत करना शामिल है। एसडीजी पर प्रयासों के समन्वय के लिए जिम्मेदार नोडल एजेंसी के रूप में नीति आयोग, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उप-राष्ट्रीय स्तर की निगरानी रूपरेखा विकसित करने में सहायता प्रदान करता है, जिससे उन्हें एसडीजी पर अध्ययन करने में मदद मिलती है। यह एसडीजी इंडिया सूचकांक के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करता है, एसडीजी स्थानीयकरण को बढ़ावा देता है, एवं राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रोत्साहित करता है।

(ख) नीति आयोग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति और चुनौतियों के अनुवीक्षण के लिए सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक रिपोर्ट जारी करता है। रिपोर्ट सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करती है, तथा विभिन्न लक्ष्यों में उनकी समग्र उपलब्धियों के आधार पर उनका मानक निर्धारित करती है। प्रत्येक राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित चुनौतियाँ भिन्न होती हैं और संबंधित सरकारों द्वारा उनका समाधान किया जाता है।

*****